3

CM धामी ने किया योजनाओं का लोकार्पण

5

संघर्ष, संगठन और नेतृत्व की प्रेरक यात्रा

6

आदिवासियों ने थाने के सामने किया चक्काजाम

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 04 प्रति सोमवार, 01 जून 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

अनुभवी प्रशासनिक नेतृत्व की नई उम्मीद, क्या राजेश राजौरा बनेंगे मध्यप्रदेश के अगले मुख्य सचिव?

सुशासन, संवेदनशीलता और परिणाम आधारित कार्यशैली ने राजौरा को बनाया मजबूत दावेदार

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश में एक बार फिर नए मुख्य सचिव को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। वर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन की अगस्त 2026 में सेवानिवृत्ति के बाद यह सवाल लगातार उठ रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश की प्रशासनिक कमान किस वरिष्ठ अधिकारी के हाथों में सौंपी जाएगी। इस चर्चा के केंद्र में जिन नामों को सबसे गंभीरता से देखा जा रहा है, उनमें अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा प्रमुख रूप से शामिल हैं। लगभग तीन दशक लंबे प्रशासनिक अनुभव, शांत कार्यशैली, संवेदनशील दृष्टिकोण और परिणामोन्मुख प्रशासनिक क्षमता ने राजेश राजौरा को प्रदेश के सबसे भरोसेमंद अफसरों की श्रेणी में खड़ा किया है। प्रशासनिक सेवा में उनका सफर केवल पदों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अनेक

ऐसे निर्णयों और योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमिका निभाई, जिनका सीधा लाभ आमजन तक पहुंचा। हालांकि 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, मोहम्मद सुलेमान, 1990 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जो केंद्र में भी प्रतिनियुक्ति पर रही अलका उपाध्याय, विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं एस.एन. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव, वन व पर्यावरण, अशोक वर्णवाल भी रेस में हैं।

प्रशासनिक अनुभव का मजबूत आधार

राजेश राजौरा उन अधिकारियों में माने जाते हैं जिन्होंने शासन और प्रशासन के लगभग हर महत्वपूर्ण पक्ष को नजदीक से समझा है। लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने नगरीय विकास, राजस्व, आधारभूत संरचना, वित्तीय प्रबंधन और लोककल्याण से जुड़े विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। उनके कार्यकाल की विशेषता यह रही कि उन्होंने हमेशा नीति निर्माण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच बेहतर संतुलन स्थापित किया। (शेष पेज 2 पर)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के जनकल्याण और सुशासन की नई दिशा में उल्लेखनीय कार्य

किसान, महिला और युवा हितैषी नीतियों से बदलता छत्तीसगढ़

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के साथ ही राज्य में सुशासन, विकास और जनकल्याण को केंद्र में रखकर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पदभार ग्रहण करते ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार का लक्ष्य राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों, आदिवासियों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।

महतारी वंदन योजना का शुभारंभ

सरकार के गठन के बाद सबसे चर्चित और लोकप्रिय निर्णय महतारी वंदन योजना का रहा। इस योजना के तहत प्रदेश की पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इससे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है तथा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग मिला है। लाखों महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलने से यह योजना महिला सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनी है।

किसानों को धान का 3100 रु प्रति क्विंटल

सरकार ने चुनावी संकल्प को पूरा करते हुए किसानों से धान खरीदी की व्यवस्था को मजबूत किया तथा किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित किया। (शेष पेज 2 पर)

किसानों के सच्चे हितैषी बने कमलनाथ, हर संकट में उठाई अन्नदाता की आवाज

कर्जमाफी से मंडी सुधार तक हर कदम किसानों के नाम

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति में जब भी किसानों के मुद्दों की बात होती है, तो पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ का नाम प्रमुखता से सामने आता है। प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है और यही कारण है कि कमलनाथ ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दी। आज जब भीषण गर्मी और अनियमित व्यवस्थाओं के कारण किसान परेशान हैं, तब एक बार फिर कमलनाथ किसानों की आवाज बनकर सामने आए हैं। हाल ही में प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं खरीदी को लेकर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर किसानों को घंटों धूप में खड़े रहना पड़ा, कहीं भुगतान में देरी हुई तो कहीं पंजीयन और तौल प्रक्रिया में अव्यवस्था देखने को मिली। इस स्थिति को लेकर कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से किसानों के लिए तत्काल राहत और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की मांग की। (शेष पेज 3 पर)

सुशासन, संवेदनशीलता और परिणाम आधारित कार्यशैली ने राजौरा को बनाया मजबूत दावेदार

(पेज 1 का शेष)

प्रदेश के कई बड़े विकास कार्यों में उनकी प्रशासनिक समझ और समन्वय क्षमता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। यही वजह है कि उन्हें सरकार और प्रशासन के बीच एक प्रभावी सेतु के रूप में भी देखा जाता है। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच उनकी कार्यशैली को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है, क्योंकि वे निर्णय लेने के साथ संवाद बनाए रखने में भी विश्वास रखते हैं।

संवेदनशील और सुलझे हुए अफसर की पहचान

राजेश राजौरा एक शांत, संतुलित और सुलझे हुए प्रशासक के रूप में जाना जाता है, जो परिस्थितियों को समझकर समाधान आधारित निर्णय लेने में विश्वास रखते हैं। कई बार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उन्होंने संयम और दूरदृष्टि का परिचय दिया। प्रशासनिक स्तर पर उनकी यही विशेषता उन्हें अन्य अधिकारियों से अलग बनाती है। शासन में लगातार बदलती प्राथमिकताओं के बीच उन्होंने हमेशा विकास और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का प्रयास किया।

केंद्र और राज्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद

यदि राजेश राजौरा को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी मिलती है, तो यह माना जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को नई गति मिल सकती है। वर्तमान समय में सरकार की प्राथमिकता केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि समय सीमा में उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राजौरा की कार्यशैली को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि वे प्रशासनिक मशीनरी को अधिक समन्वित और परिणाम केंद्रित बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की विकास प्राथमिकताओं को धरातल पर उतारने में अनुभवी प्रशासनिक नेतृत्व की बड़ी भूमिका रहने वाली है। ऐसे समय में राजेश राजौरा जैसे अधिकारी को प्रशासनिक मुखिया बनाए जाने की संभावनाओं को काफी गंभीरता से देखा जा रहा है।

विकास और सुशासन की दिशा में प्रभावी भूमिका

मध्यप्रदेश तेजी से औद्योगिक निवेश, अधोसंरचना विकास, कृषि विस्तार, डिजिटल गवर्नेंस और शहरी विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। ऐसे समय में प्रशासनिक नेतृत्व का अनुभव और दृष्टि दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राजेश राजौरा की प्रशासनिक यात्रा यह संकेत देती है कि वे बड़े विजन को धरातल पर उतारने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिनमें विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता थी। यही कारण है कि उन्हें टीमवर्क आधारित प्रशासनिक मॉडल का समर्थक भी माना जाता है। शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता को लेकर उनकी स्पष्ट सोच उन्हें प्रभावी प्रशासक के रूप में स्थापित करती है।

राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन की क्षमता

मुख्य सचिव का पद केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं होता, बल्कि यह सरकार की नीतियों और प्रशासनिक तंत्र के बीच समन्वय का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी होता है। इस पद पर ऐसे अधिकारी की आवश्यकता होती है जो राजनीतिक नेतृत्व की प्राथमिकताओं को समझते हुए प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रख सके। राजौरा की छवि एक ऐसे अधिकारी की रही है जिन्होंने हर सरकार में अपनी कार्यकुशलता और संतुलित दृष्टिकोण के कारण भरोसा अर्जित किया। वे अनावश्यक विवादों से दूर रहकर काम करने वाले अधिकारियों में गिने जाते हैं। उनकी यही कार्यशैली उन्हें प्रशासनिक स्थिरता और प्रभावी संचालन के लिए उपयुक्त बनाती है। वर्तमान समय में जब सरकार विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाना चाहती है, तब अनुभवी और संतुलित प्रशासनिक नेतृत्व की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है।

भविष्य की प्रशासनिक दिशा

मध्यप्रदेश आने वाले वर्षों में निवेश, रोजगार, कृषि, शिक्षा और शहरी विकास के कई बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में मुख्य सचिव का पद केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। राजेश राजौरा को लेकर जिस प्रकार की चर्चा सामने आ रही है, वह इस बात का संकेत है कि उन्हें एक सक्षम, अनुभवी और भरोसेमंद प्रशासनिक चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। उनकी प्रशासनिक समझ, जनहित के प्रति संवेदनशीलता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की क्षमता उन्हें इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मजबूत दावेदार बनाती है। यदि उन्हें प्रदेश का अगला मुख्य सचिव बनने का अवसर मिलता है, तो यह उम्मीद की जा रही है कि मध्यप्रदेश में सुशासन, प्रशासनिक समन्वय और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के जनकल्याण और सुशासन की नई दिशा में उल्लेखनीय कार्य

(पेज 1 का शेष)

इससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा मिली। राज्य के लाखों किसानों को इस निर्णय का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ। लंबे समय से लंबित धान बोनस की मांग को पूरा करते हुए सरकार ने किसानों को दो वर्ष का बकाया बोनस वितरित किया। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा किसानों में सरकार के प्रति विश्वास मजबूत हुआ।

प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी

गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित प्रकरणों को स्वीकृति दी गई। लाखों आवासों की मंजूरी से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों के अपने घर का सपना साकार होने लगा। सरकार ने आवास निर्माण की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने पर विशेष ध्यान दिया। वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और वनवासी परिवारों की आजीविका को मजबूत करने के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण की दरों में वृद्धि की गई। साथ ही बोनस वितरण और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया गया। इससे वन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।

युवाओं के लिए रोजगार और भर्ती प्रक्रिया

सरकार ने रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाई। विभिन्न विभागों में नियुक्तियों के लिए अभियान चलाया गया। पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य विभागों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किए गए। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन देने की दिशा में भी योजनाएं संचालित की गईं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कानून व्यवस्था को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया। अपराध नियंत्रण, महिलाओं की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर समीक्षा और सुधारात्मक कदम उठाए गए। पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में भी कार्य किए गए। सरकार ने सुरक्षा और विकास की दोहरी रणनीति अपनाते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा,

स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं का विस्तार किया। दूरस्थ आदिवासी अंचलों तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए गए। कई क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों के साथ विकास कार्यों को गति मिली।

आदिवासी विकास पर विशेष फोकस

आदिवासी बहुल राज्य होने के कारण सरकार ने जनजातीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया। छात्रावासों, आश्रमों, शिक्षा सुविधाओं और आजीविका कार्यक्रमों को मजबूत किया गया। आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए भी कई पहलें की गईं। प्रदेश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन किया गया। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। गंभीर बीमारियों के उपचार और स्वास्थ्य योजनाओं के लाभ को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।

बुनियादी ढांचे का विकास

सड़क, पुल, सिंचाई परियोजनाओं और शहरी विकास कार्यों में तेजी लाई गई। राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक विकास की नई संभावनाओं पर कार्य किया गया। बेहतर कनेक्टिविटी से ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास हुआ। सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योग जगत के साथ संवाद बढ़ाया। विभिन्न निवेशक सम्मेलनों और औद्योगिक नीतियों के माध्यम से रोजगार सृजन तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए गए। इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास के नए अवसर पैदा हुए।

सुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता

सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, जन शिकायतों के त्वरित निराकरण और डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर बल दिया। मुख्यमंत्री स्वयं विभिन्न योजनाओं की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। महतारी वंदन योजना के अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और सुरक्षा संबंधी उपायों को मजबूत करने की दिशा में कार्य किए गए। इससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी में वृद्धि हुई है।

विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार का लक्ष्य केवल योजनाओं का संचालन नहीं बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अधोसंरचना के क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। सरकार "सबका साथ, सबका विकास" की भावना के साथ राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपेक्षाकृत कम समय में कई महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी निर्णय लेकर जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। किसानों को आर्थिक संबल, महिलाओं को सम्मानजनक सहायता, गरीबों को आवास, युवाओं को रोजगार के अवसर और आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों ने सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है। सुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही यह सरकार छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

किसानों के सच्चे हितैषी बने कमलनाथ, हर संकट में उठाई अन्नदाता की आवाज

(पेज 1 का शेष)

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार को किसानों से जुड़ी योजनाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और संवेदनशील बनाना चाहिए, ताकि अन्नदाता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

कमलनाथ जैसे नेता को मुख्य धारा से अलग नहीं रख सकते

कमलनाथ की कुशलता और परिपक्वता को प्रदेश की जनता 18 माह के शासन में देख चुकी है। इन 18 माह में प्रदेश का हर वर्ग खुश था। खासकर किसानों के लिए तो वे मसीहा थे। किसानों की हर समस्या को उन्होंने हल किया था। आज ऐसे नेता को प्रदेश की राजनीति की मुख्यधारा अलग नहीं रखा जा सकता है। कांग्रेस मध्यप्रदेश से कमलनाथ को राज्यसभा भेजकर संदेश दे सकती है कि आज भी प्रदेश में कमलनाथ की जरूरत है। 2028 के चुनाव में यह कदम बहुत प्रभावी साबित होगा। इसके साथ ही पार्टी के मामलों को अपने आप साधा जा सकता है।

किसानों के दर्द को समझने वाले नेता

कमलनाथ की राजनीति का सबसे मजबूत पक्ष यह रहा है कि उन्होंने केवल भाषणों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीनी स्तर पर किसानों की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने का प्रयास किया। जब वे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने किसानों के आर्थिक संकट को गंभीरता से लिया। उनका मानना था कि यदि किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तभी प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। उनके कार्यकाल की सबसे चर्चित और ऐतिहासिक योजनाओं में से एक थी "जय किसान फसल ऋण माफी योजना"। इस योजना के माध्यम से लाखों किसानों के कर्ज माफ किए गए। उस समय प्रदेश के अनेक किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे और आत्महत्या जैसी घटनाएं भी सामने आ रही थीं। कमलनाथ सरकार ने किसानों को राहत देने के उद्देश्य से सहकारी बैंकों के ऋण माफ करने का बड़ा निर्णय लिया।

कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने की सोच

कमलनाथ केवल राहत योजनाओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में भी काम किया। उनका मानना था कि किसान केवल मेहनतकश नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का निर्माता है। इसलिए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। उनकी सरकार ने मंडियों की व्यवस्था सुधारने, फसल खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में कई कदम उठाए। किसानों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रियाओं को आसान बनाने की कोशिश की गई। कमलनाथ सरकार ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया। किसानों के लिए बिजली व्यवस्था में सुधार और कृषि पंपों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए गए।

आज भी किसानों के मुद्दों पर मुखर

राजनीति में सत्ता बदलती रहती है, लेकिन किसानों के प्रति कमलनाथ की संवेदनशीलता आज भी वैसी ही दिखाई देती है। वर्तमान समय में जब प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, तब मंडियों में किसानों को हो रही परेशानी को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जिस किसान की मेहनत से पूरा देश अन्न प्राप्त करता है, उसी किसान को यदि खुले आसमान के नीचे घंटों खड़ा रहना पड़े तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

कमलनाथ की योजनाओं को आगे बढ़ा रही वर्तमान सरकार

यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि कमलनाथ सरकार द्वारा शुरू की गई कई किसान हितैषी योजनाओं को वर्तमान सरकार भी आगे बढ़ा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी नीतियां केवल राजनीतिक घोषणा नहीं थीं, बल्कि किसानों के हित में बनाई गई व्यावहारिक योजनाएं थीं। कृषि क्षेत्र में सुधार, किसानों को राहत और मंडी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की जो सोच कमलनाथ ने प्रस्तुत की थी, वह आज भी प्रासंगिक मानी जा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा उन योजनाओं को जारी रखना इस बात का प्रमाण है कि वे योजनाएं किसानों के लिए उपयोगी और प्रभावी थीं।

किसान और कांग्रेस की पुरानी प्रतिबद्धता

कांग्रेस पार्टी का इतिहास किसानों और मजदूरों के हितों से जुड़ा रहा है। मध्यप्रदेश में कमलनाथ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा यह संदेश दिया कि सरकार का पहला दायित्व किसानों के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कमलनाथ कई बार यह कह चुके हैं कि किसान केवल वोट बैंक नहीं बल्कि देश की रीढ़ है। यही कारण है कि विपक्ष में रहते हुए भी वे लगातार किसानों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। चाहे प्राकृतिक आपदा हो, फसल नुकसान हो, बिजली संकट हो या समर्थन मूल्य का मुद्दा कमलनाथ ने हर विषय पर किसानों के पक्ष में आवाज उठाई।

समाज को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पत्रकार: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के सच्चे सेनानी हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर परिश्रम करते हुए सूचनाओं को जन-जन तक पहुंचाते हैं और समाज को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीडिया की सकारात्मक आलोचना केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि प्रशासन और सरकार को भी आत्ममंथन और बेहतर कार्य की दिशा प्रदान करती है। यह आयोजन हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि माता कौशल्या की धरती और भगवान श्रीराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की गौरवशाली परंपरा पर आधारित ऐसा अद्भुत आयोजन निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। उन्होंने आयोजन के लिए रायपुर प्रेस क्लब को बधाई देते हुए कहा कि रायपुर प्रेस क्लब देश के पुराने और प्रतिष्ठित प्रेस क्लबों में से एक है, जिसका इतिहास समृद्ध और प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता और पत्रकारों के सम्मान में आयोजित ऐसे कार्यक्रम प्रेस क्लब की प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता का सशक्त प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर की पत्रकारिता परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस शहर ने पत्रकारिता जगत को अनेक शिखर पुरुष दिए हैं। उन्होंने मधुकर खेर, मायाराम सुरजन, ललित सुरजन, रमेश नैय्यर और बबन प्रसाद मिश्र सहित अनेक प्रतिष्ठित संपादकों और पत्रकारों का स्मरण करते हुए कहा कि इन विभूतियों ने पत्रकारिता की सशक्त और वैचारिक परंपरा को समृद्ध किया है।

मुख्यमंत्री ने भारतीय सनातन परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि देवर्षि नारद को आदि पत्रकार माना जाता है और इसी कारण पत्रकार बंधु नारद जयंती को सम्मानपूर्वक मनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत रोचक और प्रेरक तथ्य है कि उदंत मार्तंड का प्रकाशन भी नारद जयंती के दिन आरंभ हुआ, जो इस बात का प्रतीक है कि भारतीय पत्रकारिता की जड़ें हमारी सांस्कृतिक चेतना और सनातन मूल्यों से गहराई से जुड़ी रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय पत्रकारिता ने राष्ट्रवादी चेतना को स्वर देने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार एवं इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर डॉ. के.जी. सुरेश ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत तक पत्रकारिता ने राष्ट्रधर्म और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने समय के साथ बदलती तकनीकों के अनुरूप स्वयं को विकसित किया है, किंतु सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और नागरिक पत्रकारिता की अवधारणा ने कई नई चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता को शोधपरक, तथ्यात्मक और साक्ष्य आधारित बनाए रखना समय की आवश्यकता है, ताकि पत्रकारिता की विश्वसनीयता और सामाजिक भूमिका और मजबूत हो सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। इसी उद्देश्य के साथ प्रदेशभर में सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था एवं पेयजल योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा जनपद सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के पूर्ण होने से जनपदवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा की जनता को इन विकास कार्यों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि उत्तराखंड सरकार जनसेवा एवं प्रदेश के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

यहां केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, जिला पंचायत अध्यक्षा हेमा गैडा, विधायक रानीखेत डॉ. प्रमोद नैनवाल, कुलपति एसएसजे विवि सतपाल सिंह बिष्ट, जिलाधिकारी अंशुल सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर आर घोड़के सहित जनप्रतिनिधि, विवि प्रशासन के अधिकारी सहित अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 138.092 करोड़ रू. की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया जिनमें 112.113 करोड़ रूपये का लोकार्पण एवं 25.979 करोड़ रूपये की योजनाओं का शिलान्यास किया।

सम्पादकीय

दिशा हत्याकांड: न्याय, संवेदनशीलता और जवाबदेही की कसौटी

भोपाल में मॉडल और अभिनेत्री दिशा शर्मा की संदिग्ध मृत्यु ने पूरे देश को झंकझोर दिया है। यह मामला अब केवल एक परिवार या एक शहर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, दहेज प्रताड़ना, वैवाहिक हिंसा और न्यायिक व्यवस्था की प्रभावशीलता पर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेने और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने से इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिशा शर्मा की मृत्यु 12 मई को भोपाल स्थित उनके ससुराल में हुई थी। प्रारंभिक जानकारी में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन परिजनों ने दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगाए। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला और मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। आज भी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह आत्महत्या थी, दुर्घटना थी या फिर सुनियोजित हत्या। यही कारण है कि निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इस मामले का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि विवाह संस्था के भीतर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समाज में लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। देश में दहेज निषेध कानून और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रताड़ना और संदिग्ध मौतों के मामले सामने आते रहते हैं। यदि किसी महिला को विवाह के बाद मानसिक, आर्थिक या सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है, तो यह केवल एक परिवार की विफलता नहीं बल्कि सामाजिक चेतना की कमी का भी प्रतीक है।

दिशा प्रकरण में जांच एजेंसियां उनके अंतिम घंटों की गतिविधियों, डिजिटल साक्ष्यों, वित्तीय लेन-देन, कथित पारिवारिक विवादों और अन्य परिस्थितियों की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। सीबीआई ने घटनाक्रम को समझने के लिए आधुनिक "टनल ब्यू" तकनीक का उपयोग भी शुरू किया है, जिससे अंतिम क्षणों की डिजिटल पुनर्रचना की जा रही है। यह जांच के बदलते स्वरूप और तकनीकी क्षमता का संकेत है।

हालांकि, इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है क्या हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी कर रहे हैं? सोशल मीडिया के दौर में आरोप और प्रत्यारोप तथ्यों से पहले सामने आ जाते हैं। इससे न केवल जांच प्रभावित होने का खतरा रहता है बल्कि न्याय की प्रक्रिया भी पूर्वाग्रहों से घिर सकती है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में न्याय का आधार भावनाएं नहीं बल्कि प्रमाण और कानून होते हैं। साथ ही, मीडिया की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीडिया का दायित्व केवल सनसनी पैदा करना नहीं बल्कि तथ्यों को जिम्मेदारी के साथ सामने लाना है। संवेदनशील मामलों में संतुलित रिपोर्टिंग न केवल पीड़ित परिवार बल्कि समाज के हित में भी आवश्यक होती है। दिशा शर्मा प्रकरण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। परिवार, समाज और संस्थाओं को मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जहां किसी महिला को अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष न करना पड़े। विवाह साझेदारी का संबंध है, दबाव और भय का नहीं। आज आवश्यकता इस बात की है कि जांच पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और वैज्ञानिक तरीके से संपन्न हो। यदि कोई दोषी है तो उसे कठोरतम दंड मिले और यदि आरोप निराधार हैं तो सत्य भी सामने आए। न्याय का वास्तविक अर्थ केवल अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि समाज के सामने सच्चाई को स्थापित करना भी है। दिशा हत्याकांड या संदिग्ध मृत्यु का यह मामला देश के लिए एक चेतावनी है कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं हो सकती। अब पूरे देश की निगाहें जांच एजेंसियों और न्याय व्यवस्था पर हैं कि वे इस मामले में सच्चाई को सामने लाकर न्याय की उम्मीदों को कितना पूरा कर पाती हैं।

सियासी गहमागहमी

क्या सच में मप्र के मुख्यमंत्री के बदलाव की सुगबुगाहट है?

मध्यप्रदेश की राजनीति में समय-समय पर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगती रही हैं। हाल के दिनों में भी कुछ राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया मंचों पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में बदलाव की चर्चाएं सुनाई दे रही हैं। हालांकि, इन अटकलों को लेकर न तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कोई संकेत मिला है और न ही प्रदेश संगठन ने ऐसा कोई संकेत दिया है। वास्तविकता यह है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार विकास, निवेश, अधोसंरचना, कृषि और रोजगार जैसे मुद्दों पर सक्रिय दिखाई दे रही है। सरकार के कामकाज और संगठन के साथ समन्वय को लेकर भी सार्वजनिक रूप से कोई असंतोष सामने नहीं आया है। भाजपा जैसी संगठन आधारित पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन का निर्णय केवल राजनीतिक चर्चाओं या अफवाहों के आधार पर नहीं, बल्कि संगठनात्मक और रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार लिया जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी सरकार के कार्यकाल के दौरान इस प्रकार की अटकलें सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। जब तक पार्टी नेतृत्व या अधिकृत मंच से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक मुख्यमंत्री परिवर्तन की चर्चाओं को केवल राजनीतिक कयास ही माना जाना चाहिए।

क्या छग के पूर्व CM भूपेश बघेल पंजाब में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे?

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या उनकी कार्यशैली कांग्रेस को मजबूती देगी या फिर पार्टी के भीतर नए विवादों को जन्म देगी। यह चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता गंवा चुकी है और वहां संगठनात्मक चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। हालांकि किसी एक नेता को किसी राज्य में पार्टी की सफलता या असफलता के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। पंजाब की राजनीति के अपने अलग सामाजिक, क्षेत्रीय और संगठनात्मक समीकरण हैं। वहां कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल-भाजपा गठबंधन के बीच अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत बनाए रखने की है। भूपेश बघेल को संगठन को सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने वाला नेता माना जाता है। लेकिन पंजाब में उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे स्थानीय नेतृत्व के साथ कितना बेहतर तालमेल स्थापित कर पाते हैं। यदि गुटबाजी पर नियंत्रण और संगठनात्मक एकता कायम करने में वे सफल रहते हैं तो कांग्रेस को लाभ मिल सकता है। वहीं यदि आंतरिक मतभेद बढ़ते हैं तो राजनीतिक नुकसान की आशंका भी बनी रहेगी।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

सांसद अभिषेक बनर्जी जी पर सोनारपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं - यह उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना, और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत है।

यह BJP की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

वरिष्ठ पत्रकार श्री अमित तिवारी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।

ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिजनों, मित्रों एवं शुभचिंतकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

-कमलनाथ

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

सम्राट चौधरी: संघर्ष, संगठन और नेतृत्व की प्रेरक यात्रा

समता पाठक/जगत प्रवाह

बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी का नाम उन नेताओं में लिया जाता है जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक पद तक का लंबा सफर तय किया है। अपनी संगठन क्षमता, स्पष्ट वक्तृत्व शैली और जनसंपर्क के कारण उन्होंने बिहार की राजनीति में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। वर्ष 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर उन्होंने राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। वे बिहार के पहले भाजपा नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को बिहार के मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में हुआ। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति के प्रभावशाली नेताओं में रहे और कई बार विधायक निर्वाचित हुए। राजनीतिक वातावरण में पले-बढ़े सम्राट चौधरी ने प्रारंभ से ही सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के प्रति रुचि दिखाई। उनकी माता का नाम पार्वती देवी है। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और युवावस्था में ही सक्रिय राजनीति का मार्ग चुन लिया।

सम्राट चौधरी की राजनीतिक यात्रा छात्र राजनीति से शुरू हुई। उन्होंने युवाओं के बीच अपनी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता के कारण जल्द ही पहचान बनाई। बिहार की राजनीति में उनका उदय उस दौर में हुआ जब राज्य सामाजिक और राजनीतिक बदलावों से गुजर रहा था। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ काम करते हुए संगठन और जनाधार दोनों को मजबूत किया। राजनीतिक जीवन के शुरुआती वर्षों में वे जनता दल और बाद में राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े रहे। इसके पश्चात उन्होंने जनता दल (यूनाइटेड) में भी कार्य किया और अंततः वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए।

भाजपा में शामिल होने के बाद उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। पार्टी नेतृत्व ने उनकी संगठनात्मक क्षमता को पहचानते हुए उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपीं। वे बिहार विधान परिषद के सदस्य बने और बाद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाली। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन विस्तार, कार्यकर्ता सशक्तिकरण और भाजपा के जनाधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार में विभिन्न विभागों का दायित्व संभाला। प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक समझ के कारण वे सरकार और संगठन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने में सफल रहे। वर्ष 2024 में उन्हें बिहार का उपमुख्यमंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार और विकास संबंधी विषयों पर सक्रिय भूमिका निभाई। अप्रैल 2026 बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक क्षण लेकर आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सम्राट चौधरी को अपना नेता चुना। 15 अप्रैल 2026 को उन्होंने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। यह पहली बार था जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुआ। उनके नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार की नई पारी शुरू हुई। सम्राट चौधरी को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो संगठन और सरकार दोनों में समान दक्षता रखते हैं। वे विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन और युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रशासनिक पारदर्शिता, निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष बल दिया है। आज सम्राट चौधरी बिहार की नई राजनीतिक पीढ़ी के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। छात्र राजनीति से लेकर मुख्यमंत्री पद तक का उनका सफर संघर्ष, धैर्य और राजनीतिक प्रतिबद्धता का उदाहरण है। उनकी यात्रा यह दर्शाती है कि संगठनात्मक समर्पण, जनसंपर्क और निरंतर मेहनत के बल पर राजनीति में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनसे राज्य के विकास और सुशासन को नई दिशा देने की अपेक्षा की जा रही है।

पीएम मोदी की अपील के मायने; क्या देश की आर्थिक स्थिति चिंताजनक है?

-विजया पाठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय-समय पर देशवासियों और आर्थिक हितधारकों से अपील करते हैं, जो केवल राजनीति नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण होती हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए वैश्विक परिदृष्य के मददेनजर कई अपीलें की हैं। जैसे सोना मत खरीदों, विदेश यात्रा मत करो, खाने के तेल का उपयोग कम करो और सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोल-डीजल का कम उपयोग करो। मोदी की इन अपीलों से लग रहा है कि देश के अंदर आर्थिक हालात बदतर हो गये हैं। आज भले ही मोदी सरकार इन आरोपों से सही नही ठहरा रही हो लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नही है। हालांकि यह अवसर नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की हो। 1962 में लाल बहादुर शास्त्री ने जब देश के अंदर अन्न की कमी थी तो उन्होंने सप्ताह में एक दिन उपवास करने की अपील की थी। 1971-73 के बीच इंदिरा गांधी ने भी "संयम, सहयोग और स्वदेशी उत्पादन" के संदेश को आगे बढ़ाया था। लेकिन उस समय के भारत और आज के भारत में काफी अंतर था। आज भारत कई मामलों में आत्मनिर्भर है। मोदी सरकार अपनी ताकत और आर्थिक स्थिति को मजबूत बताती आ रही है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोदी को अपील करने की जरूरत पड़ी। यही सवाल आज हर एक देशवासी के अंदर कुरेद रहा है। आज भारत अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितता के कारण भारत की अर्थव्यवस्था ने कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। लोगों के मन सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश 1991 जैसे हालात से गुजर रहा है। क्या मोदी सरकार आर्थिक आपातकाल लगाने की तैयारी में है। यह ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सब जानना चाहते हैं।

मुद्रास्फीति और महंगाई

खाद्य पदार्थों, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने आम जनता की क्रय शक्ति पर दबाव डाला है। रूपया 96 रूपये प्रति डॉलर के उपर जा चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है। पेट्रो पदार्थों के आयात के कारण देश की हालत खराब हो चुकी है। खासकर ईरान-अमेरिका-इजराईल युद्ध के बाद को स्थिति और खराब हुई है। वहीं मंहगाई की बात करें तो लगातार बढ़ती मंहगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। खादय पदार्थों के साथ अन्य सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं।

विनिमय दर और विदेशी निवेश

रुपए की विनिमय दर और विदेशी निवेश में अस्थिरता ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाया है। इससे स्पष्ट होता है कि देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से संकटग्रस्त है, चुनौतियों से जूझ रही है और सुधार की दिशा में तेजी की आवश्यकता है। निवेशक लगातार अपना निकाल रहे हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र अभी भी कमजोर हैं। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद किसान कई परेशानियों से जूझ रहा है। खाद, बीज जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी उत्पादन पर प्रभाव डाल रही है।

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की हलचल तेज, एनटीपीसी गाडरवारा में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर-एसपी ने संभाली कमान

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। एनटीपीसी गाडरवारा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। गुरुवार कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 5 या 6 जून 2026 को प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह नागेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया, एसडीएम गाडरवारा श्रीमती कलावती व्यारे सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने हेलीपैड स्थल, मुख्य कार्यक्रम स्थल और पार्किंग व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और सभी व्यवस्थाएं समय सीमा में पूर्ण की जाएं। निरीक्षण के दौरान कानून व्यवस्था, सुरक्षा बेरीकेटिंग, परिवहन व्यवस्था, पार्किंग, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा, फायर ब्रिगेड, पेयजल, साफ-सफाई एवं सत्कार व्यवस्था सहित सभी जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्रशासन द्वारा कार्यक्रम को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश बना गेहूं उपार्जन में देश का अग्रणी राज्य : हेमंत खण्डेलवाल

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर ऐतिहासिक कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार की किसान हितैषी नीतियों, पारदर्शी व्यवस्था और प्रभावी प्रबंधन के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश ने इस वर्ष गेहूं उपार्जन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, समय पर भुगतान और सुविधाजनक खरीदी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। प्रदेश में निर्धारित 100 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य को पार करते हुए 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का रिकॉर्ड उपार्जन हुआ, जो किसानों के विश्वास और सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह केवल रिकॉर्ड उपार्जन नहीं, बल्कि कांग्रेस द्वारा फैलाए गए भ्रम और दुष्प्रचार की भी पोल खोलता है।

लघु एवं सीमांत किसानों को मिला सबसे अधिक लाभ

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इस वर्ष विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए खरीदी व्यवस्था को मजबूत बनाया। प्रदेश में 13 लाख 41 हजार 266 से अधिक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा गया, जिनमें 8 लाख से अधिक सीमांत एवं लघु किसान शामिल हैं। किसानों को 2585 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तथा 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस सहित 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है। अब तक किसानों को 23 हजार 708 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।

पीड़ित परिवार से बदसलूकी कर रहीं थी महिला पुलिसकर्मी तो भड़के आदिवासी

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। पुलिस की नाकामियों का एक और नया उदाहारण सामने आया है जहां ग्राम भादुगांव में एक आदिवासी व्यक्ति नहर में वह जाने के 5 दिन बाद भी स्थानीय पुलिस उक्त आदिवासी व्यक्ति की तलाश नहीं कर पाए जाने को लेकर ग्राम बांदरखो के सैकडों आदिवासी महिला पुरूष पीडित परिवार के साथ थाने पहुंचा लेकिन पुलिस की कार्यशैली और संतोष जनक जबाब न मिलने से भड़क उठे और थाने के सामने टेक्टर ट्राली बीच सड़क पर खडी कर एक साईड की रोड़ जाम कर दिया। वहीं दूसरी साईड पर चक्काजाम करते हुए करीब 1 घंटे तक बैठे रहें। कुछ आदिवासी सड़क पर ही लेट कर विरोध करते नजर आये। इस दौरान पीडित परिवार की महिलाओं से चर्चा के दौरान

आदिवासियों ने थाने के सामने रोड बंद कर किया चक्काजाम

महिला पुलिसकर्मी प्रियंका पाठक ने बदसलूकी करते हुए अपनी वर्दी का रौब झाड़ने की कोशिश की जिससे आदिवासी महिला पुरूष भड़क उठे, जिन्हें कुछ पुलिसकर्मियों ने शांत कराया।

परिजनों ने लगाया हत्या करने का आरोपः आदिवासी जियालाल अपने दोस्तों के साथ भादुगांव नहर पर नहाने गया था। तभी से लापता है। परिजनों का आरोप है कि उसकी नजर में डूबोकर हत्या की गई है और लाश को बहा दिया गया है, जिससे न तो व्यक्ति का पता चला है और न ही अभी तक लाश मिली है लेकिन पुलिस ने 5 दिन बीत जाने के बाबजूद भी अब तक आदिवासी की तलाश नहीं कर सकी और न ही उन लोगों से पुछताछ की है, जिनके साथ गए नहर में नहाने गए थे। परिजनों ने कहा कि पुलिस की कार्यशैली ठीक नहीं है जिससे पीडित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है।

अपने-अपने मजहबों को तार्किक बनाएं तभी लोकतंत्र और मनुष्यता बचेगी

सारी दुनिया हिंसा की चपेट में हैं और हिंसा की आग बढ़ती जा रही है। इसका अंत कहां होगा, क्या दुनिया में कोई समझ विकसित होगी या दुनिया का एक तानाशाह होगा या दुनिया नष्ट होगी, ये विकल्प हैं जो अनुत्तरित हैं। इसका उत्तर भी किसी व्यक्ति को देना या विचार या दर्शन को देना आज सम्भव नहीं है। फिलहाल तो विश्व ताकत का विश्व बन रहा है। भारत की पुरानी कहावत शिजसकी लाठी उसकी भैंस सारी दुनिया पर चरितार्थ हो रहा है। युद्ध की आग फैलती जा रही है। पिछले तीन वर्ष रूस और यूक्रेन युद्ध के थे। रूस-यूक्रेन के दुर्लभ खनिज तत्वों पर कब्जा करने के लिए और अपने पुराने सोवियत रूस यानी यूएसएसआर जो 1986-87 में बिखर चुका है, उसे वापस लाने की योजना में है। यूक्रेन युद्ध उसी का एक हिस्सा है। अमेरिका ने भी लगभग उसी तर्ज पर यानि ताकत के दम पर लैटिन अमेरिकी देशों को अपने कब्जे में लेने का उपक्रम शुरू कर दिया है। उसकी भी दृष्टि उसी प्रकार की लगती है कि अमेरिका गोलार्ध के सभी देश अमेरिकी हिस्से हैं और लाजिमी तौर पर उन्हें अमेरिका के पीछे चलना चाहिए। इन दो महाशक्तियों का यह ताकत का खेल दुनिया को तीसरे विश्वयुद्ध की ओर ले जा रहा है। वेनेजुएला पर कब्जे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का अगला निशाना क्यूबा, ग्रीनलैंड पर है। इसके पीछे दृष्टि वहीं भूसम्पदा जो अमेरिकी विलासिता, सम्पन्नता, सामरिक शक्ति के लिए जरूरी है, उस पर कब्जा करने की है।

रघु ठाकुर
सामाजिक कार्यकर्ता, चिंतक और समाजवादी नेता

रूस-यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ देने के नाम पर अमेरिका ने यूक्रेन से युद्ध में सहयोग के खर्च की वसूली में लगभग बत्तीस लाख करोड़ के दुर्लभ खनिज पदार्थों को वसूलने का फैसला कर लिया है। अमेरिका का यूक्रेन को समर्थन कोई नैतिक या लोकतांत्रिक आधार पर नहीं है। लोकतांत्रिक दुनिया के लिए भी नहीं, बल्कि अपनी लूट के लिए इस्तेमाल करने के लिये है। जिस प्रकार जंगल में शेर अपनी अपनी सीमाओं को बांध लेते है। उसके अंदर वही शिकार कर सकते हैं। एक जमाने के दस्युदल अपने अपने इलाके बांटे हुए थे। उनके बीच वहीं लूटपाट कर सकते थे। राजे रजवाड़े अपने अपने राजपाट की सीमा बांटे हुए थे। उसी हिसाब से वहां के लोगों की राजस्व वसूली कर सकते थे। इसी प्रकार अब दुनिया का निर्माण हो रहा है जो सामरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति के आधार पर वैश्विक सीमाओं की नयी सीमा रेखाएं खींच रहे हैं। सम्भावित तीसरा युद्ध किसी तानाशाह के खिलाफ नहीं, बल्कि नया तानाशाह बनने के लिए है।

दिमागी तौर पर भी दुनिया अपने अपने मजहबी कट्टरपंथों में बंटी है। एक-दूसरे से भयभीत हैं। एक-दूसरे को साम्प्रदायिक घोषित करती हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हर मजहब में कुछ अच्छाइयां हैं, परंतु परम्परा के तौर पर कुछ कट्टरता और अंधविश्वास भी है। ताकत के दम पर सामरिक शक्तियां दूसरे देशों को गुलाम बनाने के प्रयास करती हैं। मजहब भी अपनी परंपराओं की कट्टरता तथा धर्मगुरुओं की अलोकतांत्रिक शिष्टता को स्थापित करता है। आजकल यह जुमला अमूमन सुनने को मिलता है कि हिन्दू पंथ उदार है जिसने अन्य पंथों को स्वीकार किया है। मुस्लिम भाई कहते हैं कि वे जन्मना सेक्युलर हैं क्योंकि भाजपा के खिलाफ मतदान करते हैं। ईसाई मुल्क ईसा को मानते हैं और प्रेम तथा सेवा को अपने मजहब का लक्ष्य बताते हैं। परंतु जमीनी तौर पर दुनिया में कहीं भी प्रेम और सेवा करते नजर नहीं आते। पता नहीं क्यों और कैसे मजहब का मानसिक फैलाव उस समाज के हिस्से में परंपरा के तौर पर होता रहता है। कई बार ऐसा लगता है कि इन मजहबों के के पीछे अध्ययन-अध्यापन, चिंतन-मनन- दर्शन कम है, बल्कि जन्मना पैतृक परंपरायें मुख्य कारण हैं।

मेरा तो दशकों से यह मत रहा है कि यदि दुनिया को लोकतांत्रिक बनाना है तो धर्मों का भी लोकतंत्रीकरण होना चाहिए। एक बालिग व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार होना चाहिए। जन्म से धर्म न थोपा जाये। परिपक्व आयु तक, जिसे 18 वर्ष माना गया है, उसे हिन्दू-मुसलमान-सिख-इसाई के रूप में न देखा जाये। अठारह वर्ष के बाद उसे अधिकार हो कि वह चाहे तो किसी धर्म को चुने या न चुने, यह उसका अपना अधिकार हो। धर्म भी दुनिया में या भारत में अलोकतांत्रिक मानस बनाने का माध्यम है जिसमें निष्पक्षता से ज्यादा पक्षपात ज्यादा है। किसी भी एक धर्म को मानने वाला व्यक्ति धार्मिक प्रतीकों को सम्पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। उसके अच्छे-बुरे दोनों पक्षों को स्वीकार करता है। उनकी त्रुटियों के ऊपर न उंगली उठाता है, न बोल पाता है, बल्कि उनकी सफाई देता है।

धर्म के दार्शनिक पक्ष गौण हो गये हैं, प्रतीक महत्वपूर्ण। एक हिन्दू के लिए चोटी-जनेऊ धर्म होना है पर दूसरे का भला करना परहित सरिस धरम नहिं भाईय केवल शब्द भर रह गये हैं और प्रतीक महत्वपूर्ण हो गये हैं। लगभग यही स्थिति मुसलमान भाइयों की भी है। दाढ़ी-कपड़े, पहनावा में मुस्लिम दिखना उनके लिए ज्यादा जरूरी लगता है, भले इस्लाम की किसी अच्छी बात को न स्वीकार करें। कितने मुसलमान भाई सोने से पहले पड़ोसियों की पीड़ा या भूख का पता करते हैं? केवल परम्पराएं ही मजहब बन गई हैं, दार्शनिक पक्ष शून्य हो गया है। यही स्थिति ईसाई, सिक्ख या अन्य धर्म पंथों की भी बन रही है। पिछले दिनों मैं इस्लाम को मानने वाले एक मित्र के घर ईद पर मिलने गया था। वहां काफी मच्छर थे। परंतु वे मच्छरों को मारने के लिए बिजली के करंट वाला जाला इस्तेमाल नहीं करते। उनका कहना है कि इस्लाम में जलाकर मारने पर रोक है। मैंने उनसे कहा कि मच्छरों को मारना दवा, धुंए या जाल से हो क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा कि जला कर मारने वाले के लिए दोजख की सजा है। फिर बोले-मजहब तो मजहब है। मैंने उनसे कहा इन अंधविश्वास आधारित मजहबी परंपराओं को बदलना चाहिए। वे चुप हो गए परंतु उन्हें मन से मेरी बात स्वीकार नहीं थी।

अभी कुछ दिन पहले एक और मुस्लिम भाई मिले थे। उनके बेटे-बहू के बीच 12 साल पहले तलाक हो गया है, पर दोनों ने दोबारा शादी नहीं की। हमारे मित्र अपने नाती को लेकर चिंतित थे, उससे मिलना चाहते थे जो अपनी मां के पास है। अपने नाती से मिलने के लिए वे कोर्ट में मुकदमा करने की तैयारी में हैं। मैंने उनसे कहा कि जब दोनों ने पुनर्विवाह नहीं किया और किसी छोटी-मोटी बात पर अलगाव था तो उनका दोबारा पुनर्विवाह कर देना चाहिए, ताकि नाती के प्रति आपकी और आपके बेटे की चिंताओं का हल हो सके। वह बड़े दुरूख के साथ बोले-श्क्या करें....हमारे मजहब में जो इद्दत की व्यवस्था बना दी गई है उसे कैसे तोड़ें... यह साहस मुझ में नहीं कि मैं सारे समाज का मुकाबला कर सकूं। मैंने उनसे कहा इद्दत एक परंपरा है। हो सकता है उसका आधार कभी रहा हो। बार-बार होने वाले तलाक या झगड़ों को समाप्त करने के लिए यह कठोर और अमानवीय बंधन लगाया गया हो, पर अब इसका क्या औचित्य। हमारे मुस्लिम मित्रों में भी अपनी समाज के सामने खड़े होने का सामर्थ्य नहीं। धर्मसत्ता के लिए संकीर्णता और कुछ कट्टरता जरूरी है। संकीर्णता और कट्टरता मूलतरू अलोकतांत्रिक है। मैं अमेरिका और इजरायल के द्वारा ईरान पर किए गए हमले का विरोध करता हूं। परंतु मैं हिजाब का विरोध करने वाली बेटियों को इस्लामी गार्ड के माध्यम से पीड़ित करके जेलों में डालने के भी खिलाफ हूं। हमारे मुस्लिम भाई अमेरिकी हमले का विरोध तो करते हैं, जो किया जाना चाहिए परंतु हिजाब का विरोध कर रहीं पांच हजार बच्चियों को जेल में डाले जाने का समर्थन करते हैं। वे भारत में धर्म के नाम पर मौबलिंचिंग का विरोध करते हैं, जो किया जाना चाहिए, परंतु बांग्लादेश और पाकिस्तान में वहां के अल्पसंख्यकों की मॉबलिंचिंग या ईश-निंदा कानून के नाम पर हो रही कट्टरपंथी ज्यादती को उचित मानते हैं। अपने कट्टरपंथ को तार्किक बताना और दूसरे के कट्टरपंथ को गलत बताना, यह सिलसिला चल रहा है।

मैं समझता हूं कि अब हर व्यक्ति को अपने मजहब की कट्टरपंथी परंपरा के खिलाफ खड़े होना चाहिए। हिंदू-मुसलमान अपनी-अपनी कट्टरता के खिलाफ खड़े हों। जब ऐसा होगा तभी दुनिया बेहतर हो सकती है, तभी लोकतंत्र बच सकता है। परंतु इक्कीसवीं सदी के समाज ने पीड़ाओं को भी मजहबी आधार पर महसूस करना सीख लिया है। निस्संदेह अमेरिका और इजरायल का ईरान पर हमला घोर निंदनीय है, परंतु ईरान के द्वारा खाड़ी के इस्लामी देश सऊदी अरब-बहरीन-कुवैत आदि पर हमला कैसे जायज ठहराया जा सकता है। ईरान ने इन देशों के अमेरिकी सामरिक अड्डों पर हमला किया था। परंतु इन सामरिक अड्डों का इस्तेमाल अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नहीं किया था। ईरान के हमले से सुन्नी पंथ के निर्दोष लोग मौत के शिकार हुए। लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित राष्ट्रपति पेजेस्ट्रियन ने सार्वजनिक बयान देकर माफी मांगी और अपनी इस गलती को स्वीकार किया। परंतु मजहबी नेता खामेनेई ने निर्वाचित राष्ट्रपति को पीछे कर सार्वजनिक रूप से ईरान द्वारा किए गए हमले का बचाव किया। मतलब साफ है कि ईरान में लोकतंत्र नाममात्र का है और सारी शक्ति धार्मिक मुखिया के पास है। अन्य स्थानों पर लोकतंत्र का समर्थन करने वाले और धर्मसत्ता का विरोध करने वाले मुस्लिम भाई ईरान की धर्मसत्ता का विरोध नहीं करते। हम हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्मसत्ता के खिलाफ हैं। इसके लिए दंड सहना पड़े या जान देनी पड़े, हम तैयार हैं। परंतु हम इस्लामिक या ईसाई धर्म सत्ता के भी खिलाफ हैं। और उसे भी स्वीकार नहीं करेंगे।

मेरी राय में धर्मगुरुओं और समूहों का काम इंसान को नैतिक, मानवीय, आध्यात्मिक बनाना होना चाहिए। राजनीतिक ताकत पूर्णतः निर्वाचित सत्ता के पास होनी चाहिए। दरअसल जरूरी यह है कि दुनिया को तार्किक लोकतांत्रिक मानवीय और मूल्य आधारित बनाया जाना चाहिए। परंतु कुछ यक्ष प्रश्न और यक्ष उत्तर हैं। यक्ष प्रश्न तो इतिहास में मिलते हैं, यक्ष उत्तरों की चर्चा नहीं होती।

एक प्रश्न यह है कि यह दुनिया या समाज कैसे बदले? दुनिया, समाज, परिवार और अंत में व्यक्ति को अपने आप को बदलना होगा। अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे और दुनिया को बदलना चाहेंगे तो यह असंभव कल्पना होगी।

विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) पर विशेष

सोच बदलो, धरती बचाओ: जागरूकता से बदलाव

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

हर छोटे-छोटे निर्णय में हमारी भविष्य की धारणाएँ छुपी होती हैं। जब हम अपनी रोजमर्रा की आदतों को बदलते हैं जैसे प्लास्टिक कम करने से लेकर ऊर्जा बचाने तक, तो यह बदलाव सामूहिक रूप में बड़े पर्यावरणीय परिणाम लाता है। धरती पर जीवन के लालन पालन के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। वह प्रत्येक तत्व जिसका उपयोग हम जीवित रहने के लिए करते हैं वह सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जैसे हवा, पानी, प्रकाश, भूमि, पेड़, जंगल और अन्य प्राकृतिक तत्व। आज हमारे चारों ओर के वातावरण में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, उनसे वातावरण का विनाश होता जा रहा है। पर्यावरण विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। अब इस विषय पर शीघ्र ही गंभीरता से विचार करना होगा। आने वाले समय में मानव के लिए जीवित रहना दुर्भर हो जाएगा। पूरे भूमंडल पर प्रकृति के विरुद्ध कार्य हो रहा। प्रकृति ने मानव को अन्य जीवों की अपेक्षा एक विलक्षण वस्तु "मस्तिष्क" प्रदान किया जिसका उसने दुरुपयोग किया। उसने अपने जैविक और भौतिकवाद के चक्कर में पड़कर और स्वार्थ लोलुप्तावश सम्पूर्ण प्रकृति और पर्यावरण संकलन को क्षत विक्षप्त कर दिया। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऊर्जा प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि लाखों असमय मौतों के लिए जिम्मेवार हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं से वातावरण खराब हो रहा है। नदियों और तालाबों का जल प्रमोद के बजाय जीवन लीलने वाला बन गया है। यह बात सर्वविदीत है कि प्राकृतिक साधन सीमित है। एक न एक दिन ये सभी समाप्त हो जाएंगे अतः आवश्यक हो गया है कि बाल्यकाल से ही पर्यावरण संतुलन का ज्ञान देना आवश्यक हो गया है। जिससे उसके दिलों दिमाग मे यह बात धर कर ले कि संतुलित पर्यावरण ही उसके सुखी और सुरक्षित जीवन का एक मात्र विकल्प है। आस पास के वृक्षों, फूलों, पक्षियों, पहाड़ों, नदियों, समुद्र तटों और उसके जीव जंतुओं तथा वन्य पशुओं के महत्व को समझाना आवश्यक है तभी लोग उनका संरक्षण कर सकेंगे। व्यक्ति जिस परिवेश में जन्म लेता है, फलता फूलता है और जिस वातावरण में उसका लालन पोषण होता है, उस वातावरण की जानकारी मनुष्य के विकास के लिए अति आवश्यक है।

प्राकृतिक संतुलन लिए जागरूक पैदा करना, व्यक्तियों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की रुचि जगाना, वातावरण बिगाड़ने वाले कारणों की पहचान कराना आदि आज बहुत आवश्यक हो गया है। पर्यावरण के प्रति जनचेतना का उद्देश्य वायु प्रदूषण की समास्याओं से लोगों का अवगत कराना है जिससे वे वायु प्रदूषण को रोकने में अपना सक्रिय योगदान कर सके और आने वाले खतरों से सचेत रहें। जल प्रदूषण का निराकरण करने के लिए छात्रों के साथ चर्चा करना चाहिए। इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जनता को समुचित रूप से शिक्षित करना होगा ताकि ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हो सके। भू प्रदूषण की समस्या भी गंभीर समास्याओं में से एक है जिसका निराकरण भी होना आवश्यक है। इसके लिए हमें चाहिए कि जनजागृति पैदा की जाए ताकि लोग इधर उधर जगह जगह पर थूके नहीं और गन्दगी नही फैलाएं। अपने घरों के पास पेड़ पौधों के लिए जगह छोड़ें। घास के खुले मैदान नहीं छोड़ेंगे तो भू प्रदूषण भी फैलेगा।

पर्यावरण सरंक्षण हेतु जनसाधारण को खासकर छात्रों को इसके लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बालकों में मनोवैज्ञानिक तरीके से और दर्शन के आधार पर प्रकृति प्रेम की चेतना पैदा करनी चाहिए। ऐसे तरीकों से पढ़ाना चाहिए जिससे किसी भी खोज के बाद उसके अदुभूत तथ्यों की जानकारी उन्हें (छात्रों) को दे सकें। बालकों को देश में फैलते नाना प्रकार के प्रदूषणों के फैलने के विषय मे भी जानकारी देनी चाहिए। लोगों को आभास कराना है कि वह उस व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं जिसमे पर्यावरण शामिल है। पर्यावरण संबंधित समास्याओं के समाधान में जिम्मेदारी का भी अवबोधन कराना चाहिए।

प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आदि समास्याओं सरंक्षण तभी संभव होगा जब पर्यावरण सम्बंधी जनचेतना होगी। यह बात नही भूलना चाहिए कि इस पर्यावरण ने सारी सृष्टि को सदियों से बचाए रखा है। यदि हम स्वयं को या श्रृष्टि को बचाए रखना चाहते हैं तो पर्यावरण को सरकार के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जलवायु बदल रही है, हमने थोडे न तापमान बढ़ाया है ये सब तो सरकारों का काम है। मेरे सिर्फ अकेले से क्या होगा। ऐसे सोच से बचना चाहिए। स्वार्थपूर्ण प्रवृति वालों के ये बोल अक्सर सुनने को मिलता है लेकिन ये नुकसानदेह है। एक एक व्यक्ति को पर्यावरण बचाने के लिए आगे आना चाहिए। हमें यह समझना जरूरी है कि सबकुछ सरकारें नहीं कर सकतीं। हमारी भी जिम्मेदारी है। जो काम सरकारों का है वह करती रहें लेकिन ये धरती हमारी है इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। परिवर्तन की शुरुआत एक-एक व्यक्ति की सोच से होती है। जब सोच बदलेगी तभी धरती की हालत बदलेगी। आइए आज ही एक कदम उठाएँ, क्योंकि हमारी छोटी-छोटी आदतें ही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध धरती बनायेंगी।

मीम्स के मुखौटे में छिपा युवाओं का दर्द: 'कॉकरोच जनता पार्टी' और व्यवस्था का यथार्थ

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

तपती गर्मियों में भारत के डिजिटल क्षितिज पर एक ऐसा अभूतपूर्व तूफान उठा है, जिसने देश के स्थापित राजनेताओं और नीति-निर्माताओं को हैरत में डाल दिया है। यह तूफान किसी पारंपरिक राजनीतिक दल या रसूखदार चेहरे का नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की गलियों से उपजे एक डिजिटल आंदोलन का है, जिसका नाम है- 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP)। 16 मई 2026 को शुरू हुए इस आंदोलन ने महज कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन (2 करोड़) से अधिक फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। ऊपरी तौर पर एक मजाकिया 'मीम' और तीखे व्यंग्य जैसा दिखने वाला यह आंदोलन असल में भारत के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की गहरी निराशा और व्यवस्था के प्रति उनके संचित आक्रोश की सामूहिक हुंकार है। पुलिस सेवा के अपने लंबे कार्यकाल और प्रशासनिक समन्वय के अनुभवों में मैंने समाज के हर रंग को बहुत करीब से देखा है। वर्दी में रहते हुए मैंने महसूस किया कि कानून-व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेशेवर अपराधी नहीं होते; बल्कि वे गुमराह और हताश युवा होते हैं जिनकी ऊर्जा को सही दिशा और न्यायपरक मंच नहीं मिल पाता। आज जब मैं इस डिजिटल विद्रोह का एक प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करता हूँ, तो मुझे इसमें केवल एक इंटरनेट ट्रेंड नहीं, बल्कि देश की दुखती रगों पर हाथ रखता एक गंभीर नीतिगत यक्ष प्रश्न दिखाई देता है।

उपहास से उपजा जनसांख्यिकीय असंतोष

इस आंदोलन की शुरुआत आत्म सम्मान पर लगी एक गहरी चोट का परिणाम है। 15 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं के संदर्भ में कथित तौर पर 'कॉकरोच' और 'समाज के परजीवी' जैसे प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ (हालांकि बाद में न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण भी आया)। लेकिन यह टिप्पणी उन करोड़ों युवाओं के सीने में तीर की तरह चुभ गई जो सालों से परीक्षा की तैयारियों में अपनी जवानी खपा रहे हैं। इसके विरोध में अगले ही दिन राजनीतिक रणनीतिकार अभिजीत दिपके ने व्यंग्यात्मक लहजे में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के गठन की घोषणा कर दी, जिसका स्लोगन दिया गया—"चॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड" (आलसी और बेरोजगारों की आवाज)। युवाओं ने इस उपहास को ही अपना हथियार बना लिया क्योंकि उनका मानना है कि वे हर विपरीत परिस्थिति, पेपर लीक और प्रशासनिक लाठियों को झेलकर भी संघर्ष के मैदान में 'जिंदा' रहने का माद्दा रखते हैं।

आंकड़ों की गवाही: क्यों आक्रोशित है युवा?

यह आक्रोश बिना किसी ठोस आधार के नहीं है, इसके पीछे आर्थिक और प्रशासनिक प्रणालियों के कुछ कड़वे आंकड़े हैं। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट (जनवरी-मार्च 2026 तिमाही) के अनुसार, भारत में 18 से 29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर बढ़कर 15% के चिंताजनक स्तर पर पहुँच गई है, जिसमें शहरी क्षेत्रों के शिक्षित स्नातक सबसे अधिक प्रभावित हैं। इसके साथ ही, देश के केवल 4.2% कार्यबल के पास ही औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण है, जो कौशल विकास की कमी को दर्शाता है। इस बेरोजगारी पर कोढ़ में खाज का काम किया है बार-बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा निरस्तीकरण के दंश ने। NEET परीक्षा विवाद से लेकर विभिन्न राज्य व केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं के ध्वस्त होने से युवाओं का परीक्षा तंत्र पर से भरोसा उठ गया है। जब एक युवा कर्ज लेकर तैयारी करता है और अंत में परीक्षा निरस्त हो जाती है, तो वह केवल एक अवसर नहीं खोता, बल्कि अवसाद और सामाजिक शर्म के दलदल में धंस जाता है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य और इतिहास का सबक

इतिहास गवाह है कि जब भी युवाओं की निराशा को रचनात्मक मंच नहीं मिला, तब-तब ऐसे ही प्रतीकात्मक आंदोलनों ने व्यवस्था हिला दी हैं।

ट्यूनीशिया और अरब स्प्रिंग (2010-11): एक शिक्षित लेकिन बेरोजगार फल विक्रेता के प्रशासनिक उत्पीड़न के खिलाफ आत्मदाह ने सोशल मीडिया के माध्यम से वह जन-आक्रोश पैदा किया जिसने वहाँ की सत्ता का तख्तापलट कर दिया।

नेपाल का जन आंदोलन (2006): अप्रैल 2006 में युवाओं के नेतृत्व में चले 19 दिनों के ऐतिहासिक आंदोलन ने राजशाही को समाप्त कर लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी थी।

ये वैश्विक और ऐतिहासिक उदाहरण बताते हैं कि युवाओं का असंतोष यदि सही समय पर नीतिगत सुधारों में न बदला जाए, तो वह देश को अस्थिरता की ओर ले जा सकता है।

अधिकार, जिम्मेदारी और संतुलन की राह

आज देश, समाज और सरकार तीनों को एक मंच पर आकर इस आंदोलन के निहितार्थों को समझना होगा। जहाँ एक तरफ सरकार की यह नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह युवाओं को पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, सख्त 'एंटी-पेपर लीक कानून' और सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्रदान करे, वहीं समाज के बुजुर्गों को भी युवाओं को 'आलसी' या 'रील बनाने वाली पीढ़ी' कहना बंद कर उनके मानसिक संघर्ष को सहानुभूति से समझना होगा। दूसरी ओर, युवाओं के लिए भी यह आत्ममंथन का समय है। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इस आक्रोश को किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाने या अराजकता की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। लोकतंत्र में बदलाव रचनात्मक दबाव से आता है, उपद्रव से नहीं। इस ऊर्जा को एक मजबूत 'दबाव समूह' के रूप में विकसित होना चाहिए जो नीतिगत सुधारों के लिए शांतिपूर्ण संवाद का मार्ग चुने। 'कॉकरोच जनता पार्टी' के समर्थकों का एक लोकप्रिय डिजिटल पोस्टर कहता है "उन्होंने हमें कुचलने की कोशिश की, लेकिन वे भूल गए कि कॉकरोच परमाणु हमले में भी जिंदा रह सकते हैं।" यह पंक्ति भारतीय युवाओं की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है। इस आंदोलन ने यमुना सफाई जैसे अभियानों के जरिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी की झलक भी दिखाई है। भारत वर्तमान में 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' (युवा आबादी के लाभांश) के स्वर्णिम काल में है। यदि हम इस ऊर्जा को तिरस्कृत करने या डिजिटल सेंसरशिप से दबाने का प्रयास करेंगे, तो यह वरदान 'डेमोग्राफिक डिजास्टर' में बदल सकता है। नीति-निर्माताओं के लिए यह एक चेतावनी है कि वे इस 'मौन क्रांति' की हँसी के पीछे छिपे आंसुओं को पहचानें और इस अप्रतिम युवा ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण, नवाचार और निष्पक्ष रोजगार प्रणालियों की ओर मोड़ें।

रेल विकास को मिल रही डबल इंजन की रफ्तार

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

₹ रेल बजट

₹6,900 करोड़ (2025-26)

10 वर्षों 22 गुना की वृद्धि

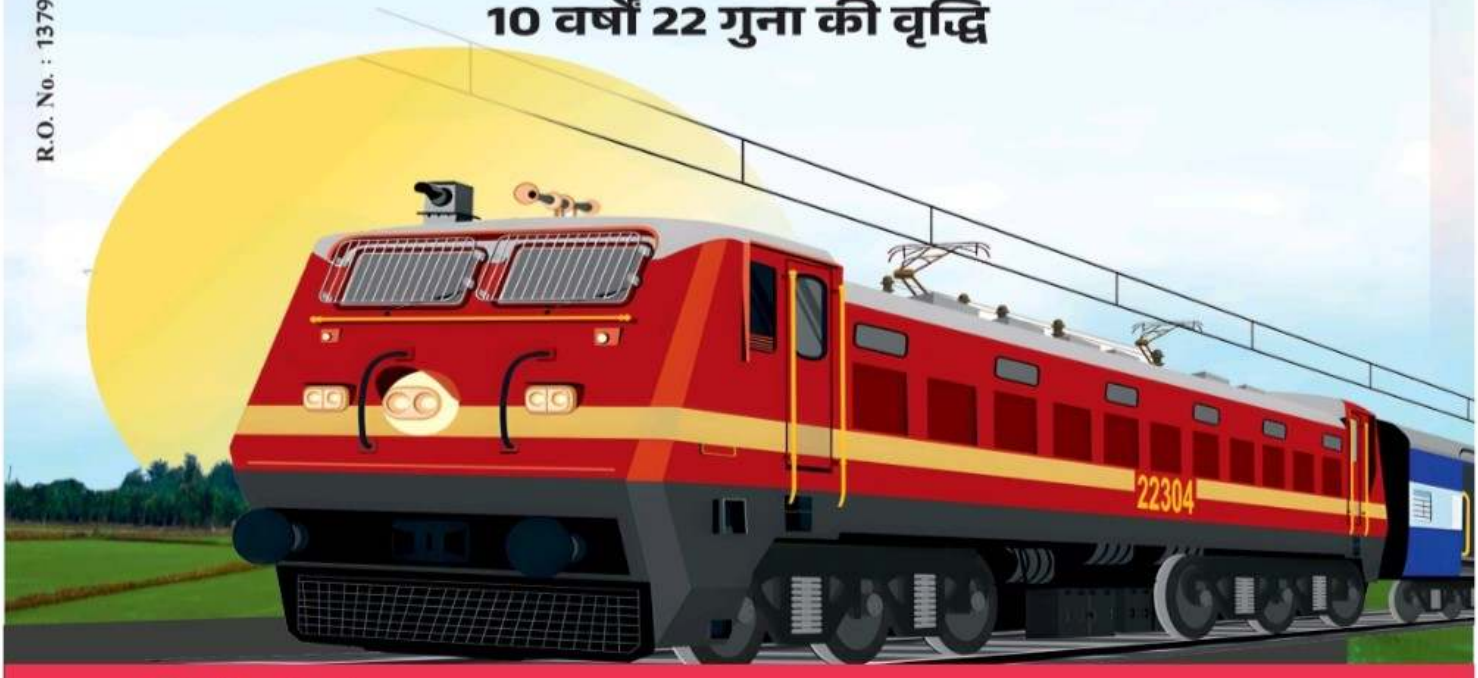

R.O. No. : 13795/ 2

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)